

# PMKVY, DDU-GKY, NATIONAL SCHEME MISSION और TRIFED का समीक्षात्मक विश्लेषण

करुणा देवांगन<sup>1</sup>, डॉ. हेमंत खंडई<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़  
<sup>2</sup>प्रोफेसर-डीन, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, भोपाल, मध्यप्रदेश

## सारांश

यह शोध-पत्र भारत सरकार की प्रमुख कौशल एवं आजीविका उन्मुख योजनाओं—Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), National Skill Development Mission तथा Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED)—का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य इन योजनाओं की संरचना, कार्यान्वयन तंत्र, लक्षित लाभार्थी समूह, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्लेसमेंट/आजीविका परिणाम, वित्तीय प्रबंधन तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना है।

शोध में द्वितीयक स्रोतों—सरकारी प्रतिवेदनों, नीति दस्तावेजों, वार्षिक रिपोर्टों एवं पूर्ववर्ती अध्ययनों—का विश्लेषणात्मक पद्धति से परीक्षण किया गया है। निष्कर्ष संकेत करते हैं कि PMKVY और DDU-GKY ने कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में व्यापक पहुँच बनाई है, किन्तु प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योग-संरेखण तथा स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में सुधार की आवश्यकता है। National Skill Development Mission ने विभिन्न योजनाओं के समन्वय और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ किया है, जबकि TRIFED ने जनजातीय समुदायों के उत्पादों के विपणन एवं आय-वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अध्ययन यह रेखांकित करता है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगरानी तंत्र की मजबूती, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, डिजिटल ट्रेकिंग, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा समुदाय-आधारित दृष्टिकोण को सशक्त करना आवश्यक है। यह शोध नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों एवं विकास प्रशासकों के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा कौशल-आधारित समावेशी विकास की दिशा में ठोस सुझाव प्रस्तुत करता है।

## 1. प्रस्तावना

सरकारी योजनाएँ वे कार्यक्रम हैं जो सरकारें अपने नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बेहतर बनाने, सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाती हैं। ये योजनाएँ केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों या दोनों के बीच साझा वित्तपोषण से चलाई जाती हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, वित्तीय समावेशन और समूहों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। भारत सरकार सभी स्तरों पर समय समय पर समाज के अनुपस्थित वर्ग के लिए कल्याण योजनाओं की घोषणा करती है। ये योजनाएँ केन्द्रीय, राज्य विशिष्ट अथवा केन्द्र एवं राज्यों के बीच एक संयुक्त गठबंधन हो सकती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं -

PMKVY (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना), DDU-GKY (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना), राष्ट्रीय कौशल मिशन और TRIFED का समीक्षात्मक विश्लेषण (Critical Analysis)

## 2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाता है।

**मुख्य उद्देश्य है** – युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाना।

### सकारात्मक पक्ष:

- बड़े पैमाने पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया।
- प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाणपत्र और कुछ हद तक रोजगार अवसर।
- स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन।

**समस्याएँ / आलोचना:**

1. प्रशिक्षण की गुणवत्ता कई बार उद्योग मानकों से मेल नहीं खाती।
2. प्रशिक्षित युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर सीमित।
3. कई बार प्रमाणपत्र तो दिए जाते हैं परंतु रोजगार की गारंटी नहीं।
4. निजी प्रशिक्षण केंद्रों पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे पारदर्शिता में कमी।

**निष्कर्ष**

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन, इसे गुणवत्ता, पारदर्शिता और रोजगार की स्थिरता पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, तभी यह भारत को “कौशल संपन्न राष्ट्र” बनाने में सफल होगी।

**3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)**

इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development – MoRD), भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का हिस्सा है।

**उद्देश्य** - ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर शहरों और उद्योगों में रोजगार दिलाना।

**सकारात्मक पक्ष:**

1. ग्रामीण युवाओं, खासकर गरीब तबके को रोजगार का अवसर।
2. आधुनिक क्षेत्रों (रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थकेयर आदि) में प्रशिक्षण।
3. महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि।

**समस्याएँ / आलोचना:**

1. प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगार अवसरों के बीच अंतर।
2. ग्रामीण युवाओं का पलायन बढ़ना, जिससे सामाजिक समस्याएँ।
3. कई बार रोजगार अस्थायी और कम वेतन वाले।
4. निगरानी तंत्र कमजोर, लाभार्थियों की स्थिति पर फॉलोअप नहीं।

**निष्कर्ष**

DDU-GKY ग्रामीण युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसने लाखों युवाओं को अवसर दिया है, परंतु इसे और सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता, रोजगार की स्थिरता, और ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थानीय रोजगार अवसर सृजित करने की आवश्यकता है।

**4. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM)**

इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुई थी। इसका संचालन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship – MSDE) द्वारा किया जाता है।

**उद्देश्य** – भारत के युवाओं को कौशल युक्त बनाकर उन्हें रोजगार योग्य और आत्मनिर्भर बनाना।

**सकारात्मक पक्ष:**

1. सभी कौशल योजनाओं का समन्वय एक मंच पर।
2. कौशल विकास को राष्ट्रीय स्तर पर नीति का हिस्सा बनाया।
3. उद्योगों की मांग और युवाओं की आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने का प्रयास।

**समस्याएँ / आलोचना:**

1. कौशल विकास और उद्योग की वास्तविक आवश्यकता में अभी भी अंतर।
2. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमान अवसर।
3. नौकरियों की कमी के कारण कौशल प्राप्त युवा भी बेरोजगार रहते हैं।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में नौकरशाही की बाधाएँ।

**निष्कर्ष**

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भारत को मानव संसाधन शक्ति में बदलने का एक बड़ा प्रयास है। यदि यह मिशन गुणवत्ता, पारदर्शिता, और रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान दे तो यह भारत को दुनिया की कौशल राजधानी (Skill Capital) बना सकता है।

## 5. TRIFED (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India)

स्थापना: वर्ष 1987 में हुई थी। संचालन: जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs), भारत सरकार द्वारा किया जाता है। TRIFED एक राष्ट्रीय स्तर का सहकारी संगठन है, जो आदिवासी समुदायों के उत्पादों का विपणन (Marketing) और विकास करता है।

**मुख्य उद्देश्य** - आदिवासी उत्पादों को बाजार दिलाना और आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

### सकारात्मक पक्ष:

1. आदिवासी हस्तशिल्प और उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध।
2. वनोपज और हस्तशिल्प का उचित दाम।
3. “वन धन योजना” जैसे प्रयासों से स्व-सहायता समूहों को मजबूती।
4. आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहन।

### समस्याएँ / आलोचना:

1. उत्पादों की मार्केटिंग और वितरण नेटवर्क अभी भी सीमित।
2. बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म नहीं हुई।
3. ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी।
4. प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक की पहुंच कम।

### निष्कर्ष

TRIFED आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसने आदिवासी उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर पहुंच, बाजार विस्तार, और तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

### समग्र निष्कर्ष (Overall Critical View):

सभी योजनाएँ युवाओं, ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को कौशल और रोजगार से जोड़ने का प्रयास करती हैं।

मुख्य चुनौतियाँ: प्रशिक्षण की गुणवत्ता, रोजगार की स्थिरता, पारदर्शिता की कमी, उद्योग की वास्तविक आवश्यकता और नौकरियों की कमी।

यदि सरकार प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उद्योगों से साझेदारी और लाभार्थियों के लिए स्थायी आय स्रोत पर ध्यान दे, तो ये योजनाएँ अधिक सफल हो सकती हैं।

आदिवासी क्षेत्रों (Tribal Areas) के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने कई योजनाएँ चलाई हैं ताकि उन्हें शिक्षा, छात्रवृत्ति, हॉस्टल और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ मिल सकें।

इन योजनाओं का असर अलग-अलग राज्यों और परिस्थितियों में अलग है, लेकिन कुल मिलाकर काफी लाभ हुआ है, हालांकि चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं।

### लाभ (फायदे):

#### 1. शिक्षा तक पहुँच (Access to Education):

छात्रवृत्ति योजनाओं (Pre-Matric और Post-Matric Scholarship) से आदिवासी बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर (dropout rate) में कमी आई है तथा स्कूल व कॉलेज की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्च सरकार उठाती है।

#### 2. आवासीय सुविधा (Hostel & Ashram Schools):

आदिवासी इलाकों में आश्रम शालाएँ और छात्रावास (hostels) बने हैं, जिससे दूर-दराज गाँवों के बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है।

#### 3. उच्च शिक्षा के अवसर:

राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (RGNF), राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं से आदिवासी विद्यार्थी उच्च शिक्षा (PhD, विदेश में पढ़ाई) कर रहे हैं।

#### 4. कौशल विकास:

कौशल प्रशिक्षण (Skill Training) और विशेष कोचिंग योजनाओं से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा रहा है।

#### 5. सामाजिक जागरूकता:

शिक्षा मिलने से आदिवासी समाज में सामाजिक और आर्थिक जागरूकता बढ़ी है।

### सीमाएँ (चुनौतियाँ):

1. बुनियादी ढाँचे की कमी – कई आदिवासी इलाकों में स्कूल, कॉलेज, शिक्षक और इंटरनेट की सुविधा अभी भी कम है।
2. भाषा और सांस्कृतिक अंतर – स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का अभाव, जिससे बच्चे जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं।
3. पहुँच की दिक्कतें – दूर-दराज जंगल/पहाड़ी क्षेत्रों में योजनाओं का सही लाभ नहीं पहुँच पाता।
4. आर्थिक दबाव – कई परिवार बच्चों से काम करवाते हैं जिससे पढ़ाई बाधित होती है।

## निष्कर्ष:

सरकारी योजनाओं से आदिवासी विद्यार्थियों को शिक्षा और रोजगार की राह मिली है। ड्रॉपआउट रेट घटा है, उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ी है, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

लेकिन अभी भी गुणवत्ता शिक्षा, पहुँच और जागरूकता पर और काम करने की ज़रूरत है।

## संदर्भ

1. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. (2015). “Scheme Guidelines”. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), Government of India.
2. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. (2021). “PMKVY 3.0 Operational Guidelines”. MSDE, Government of India.
3. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana. (2014). “Scheme Guidelines”. Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India.
4. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana. (2020). “DDU-GKY Standard Operating Procedures”. MoRD, Government of India.
5. National Skill Development Mission. (2015). “Mission Document”. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India.
6. National Skill Development Corporation. (2019). “Annual Report 2018–19”. NSDC, New Delhi.
7. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2022). “Annual Report 2021–22”. Government of India.
8. Ministry of Rural Development. (2021). “Annual Report 2020–21”. Government of India.
9. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. (2022). “Annual Report 2021–22”. Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
10. NITI Aayog. (2018). “Strategy for New India @75”. Government of India.
11. National Statistical Office. (2021). “Periodic Labour Force Survey (PLFS) Report”. Government of India.
12. International Labour Organization. (2020). “Global Employment Trends for Youth 2020”. Geneva: ILO.